

दिनांक 04.01.2018 को निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत चयनित एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 एवं डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्टों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति साथ में संलग्न है।

कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा दिनांक 09.12.2017 को समीक्षा बैठक की गयी थी, जिसमें कन्सलटेन्टों द्वारा किये जा रहे कार्यों पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी थी तथा समस्त एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 कन्सलटेन्टों को प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर, 2017 तक प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे।

हाऊसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन:-

1. मै0 स्टेसलिट सिस्टम्स लि0:-मै0 स्टेसलिट सिस्टम्स लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको चार क्लस्टर (अलीगढ़, मिर्जापुर, फैजाबाद, कानपुर,) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 48820 आवासों की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 133 नगर निकायों में से 104 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 29 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम0आई0एस0 एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 35351 की एन्ट्री की जा चुकी है तथा शेष 13429 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 5224 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 104 नगर निकायों में प्रमाणीकरण पश्चात् कुल 19782 लाभार्थी पात्र पाये गये। इस पर क्लस्टरवार सूची सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए सूडा मुख्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 20 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कराये।
2. मै0 विजन ई.आई.एस. कन्सलटिंग प्रा0लि0:-मै0 विजन ई.आई.एस. कन्सलटिंग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (इलाहाबाद, झाँसी, सहारनपुर) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 39679 आवासों की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 89 नगर निकायों में से 33 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 56 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम0आई0एस0 एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 21596 की एन्ट्री की जा चुकी है तथा शेष 18083 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 161 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 33 नगर निकायों में प्रमाणीकरण पश्चात् कुल 11000 लाभार्थी पात्र पाये गये, जिसमें से 3000 का डाटा डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को हस्तगत किया जा चुका है। इस पर क्लस्टरवार सूची सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए सूडा मुख्यालय को अवगत

क्रमशः.....2 पर

कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 20 जनवरी, 2018 तक पूर्ण करायें।

3. **मै० रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०**—मै० रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (चित्रकूट, मेरठ, मुरादाबाद) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 50675 आवासों की डी०पी०आर० भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 128 नगर निकायों में से 116 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 12 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम०आई०एस० एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 27609 की एन्ट्री की जा चुकी है तथा शेष 23066 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 1034 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दो दिवस के अन्दर सही संख्या सूझा मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी। इस पर लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) का डाटा चेक कर अपर निदेशक, सूझा य कार्यक्रम अधिकारी, सूझा को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 20 जनवरी, 2018 तक पूर्ण करायें।
4. **मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया प्रा०लि०**—मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया प्रा०लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको चार क्लस्टर (आजमगढ़, बरेली, बस्ती, देवीपाटन) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 37873 आवासों की डी०पी०आर० भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 119 नगर निकायों में से 73 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 46 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम०आई०एस० एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 24737 की एन्ट्री की जा चुकी है तथा शेष 13136 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 4442 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 73 नगर निकायों में प्रमाणीकरण पश्चात् कुल 13502 लाभार्थी पात्र पाये गये, जिसे डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को उपलब्ध कराया जाना है। इस पर क्लस्टरवार सूची सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए सूझा मुख्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 25 जनवरी, 2018 तक पूर्ण करायें।
5. **मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट प्रा०लि०**—मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट प्रा०लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको चार क्लस्टर (आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 86603 आवासों की डी०पी०आर० भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 166 नगर निकायों में से 102 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 64 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम०आई०एस० एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 58524 की एन्ट्री की जा चुकी है

तथा शेष 28079 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 10499 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 102 नगर निकायों में प्रमाणीकरण पश्चात् कुल 34676 लाभार्थी पात्र पाये गये, जिसे डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को उपलब्ध कराया जाना है। इस पर क्लस्टरवार सूची सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए सूडा मुख्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 25.01.2018 तक पूर्ण कराये।

डी0पी0आर0 / पी0एम0सी0:-

1. मै0 क्रिएटिव कन्सॉटियम:-मै0 क्रिएटिव कन्सॉटियम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 17194 आवासों की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 522 आवासों की जियो टेगिंग की जा चुकी है। जबकि एम0आई0एम0 पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर आवासों के जियो टेगिंग की सूचना शून्य है। इस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा सर्वेयर्स की संख्या बढ़ाते हुए युद्धस्तर पर जियो टेगिंग कराते हुए ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया गया।
2. मै0 रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0:-मै0 रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (मुरादाबाद, चित्रकूट, नेरठ) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 50675 आवासों की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 395 आवासों की जियो टेगिंग की जा चुकी है। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. मै0 स्नो फाउण्टेन कन्सलटेन्ट्स:-मै0 स्नो फाउण्टेन कन्सलटेन्ट्स के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 74341 आवासों की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 6720 आवासों की जियो टेगिंग की जा चुकी है। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टेगिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।
4. मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया प्रा0लि0:-संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (आगरा, गोरखपुर, वाराणसी) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 54828 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 1738 आवासों की जियो टेगिंग की जा चुकी है। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टेगिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।
5. मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट प्रा0लि0:-संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (अलीगढ़, बरेली, मिर्जापुर) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक

कुल 47590 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 62 आवासों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। कार्य की अत्यन्त धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैगिंग कराते हुए ग्राउण्डिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।

6. मै0 स्पेस कम्बाइन:- संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको एक क्लस्टर (सहारनपुर) आवंटित किया गया था, जिसमें अब तक कुल 10525 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 272 आवासों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैगिंग कराते हुए ग्राउण्डिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।
7. मै0 वॉफ्कास लि0:- संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको एक क्लस्टर (झाँसी) आवंटित किया गया था, जिसमें अब तक कुल 8497 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 337 आवासों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। कार्य की अत्यन्त धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैगिंग कराते हुए ग्राउण्डिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देश दिये गये:-

(क) हाऊसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन हेतु:-

1. शत-प्रतिशत एम0आई0एस0 एन्ट्री का कार्य दी गयी डेड लाईन के अन्तर्गत पूर्ण कराये।
2. अमान्य आधार की दशा में डाटा चेक कर समयान्तर्गत सही कराये।
3. प्रतिदिन एम0आई0एस0 एन्ट्री व अमान्य आधार की प्रगति एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट श्री हितेश पाठक को उपलब्ध कराये तथा उक्त प्रगति प्रत्येक 03 दिन में एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाये।
4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) घटक से सम्बन्धित प्रमाणित डाटा डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए अवगत कराये।
5. नियमित समयान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु संस्था का वर्क प्लान सूडा को उपलब्ध कराये।
6. बीएलसी(एन) घटक के प्रमाणीकरण का कार्य दिनांक 20 जनवरी, 2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लें। ए0एच0पी0 एवं सीएलएसएस घटक के लाभार्थियों की सूची जनवरी, 2018 तक उपलब्ध कराये।

(ख) डीपीआर/पीएमसी हेतु:-

1. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) घटक के अन्तर्गत प्लान ऑफ एक्शन कन्सलटेन्ट से प्राप्त लाभार्थियों की डीपीआर तैयार कराये।
2. स्वीकृत डीपीआर के लाभार्थियों का शत-प्रतिशत अटैचमेन्ट माह जनवरी तक पूर्ण कराये।
3. जियो टैगिंग के कार्य में तत्काल वांछित प्रगति लाई जाये।



4. कच्चे आवासों को चिन्हित कर बिना तोड़े चूना डालकर जियो टैगिंग करा दी जाये, जिसे कालान्तर में लाभार्थी द्वारा अन्यत्र अस्थायी आवास की व्यवस्था कर आवास निर्माण का कार्य कराया जाये।
5. प्रत्येक लाभार्थी की पासबुक जियो टैगिंग से पूर्व तैयार की जानी है।
6. जियो टैगिंग हेतु स्थानीय स्तर पर नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी का नाम, निवास का पता तथा मोबाइल नम्बर तत्काल सूडा में एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट श्री हितेश पाठक को उपलब्ध कराया जाये।
7. जनपदवार रखे गये समस्त नियुक्त किये गये स्टॉफ की संख्या व जियो टैगिंग हेतु उपलब्ध कराये गये मोबाइल फोन सिम कार्ड सहित का विवरण भी तत्काल उपलब्ध कराये।
8. सूडा से पांच अधिकारी/कर्मचारी को 18 वलस्टर आवंटित किये जाये, जिससे वह प्रतिदिन जनपदों से सूचना प्राप्त कर मुख्यालय में अपडेट करें तथा जियो टैगिंग में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे।
9. डीपीआर/पीएमसी का व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाये, जिसमें कन्सलटेन्ट्स के प्रतिनिधि, परियोजना अधिकारी शामिल होंगे। कन्सलटेन्ट द्वारा प्रतिदिन जनपदवार जियो टैगिंग की रिपोर्ट ग्रुप पर अपलोड करायी जायेगी, जिसे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
10. इस वर्ष लगभग एक लाख आवासों को पूर्ण किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कर लें।
11. शासन/सूडा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जनपद का औचक निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

अन्त में सभी एचएफएपीओए व डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि समय सीमान्तर्गत कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

संख्या:-3884 /01/29/एचएफए-12/2017-18 दिनांक 09 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त हाऊसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन कन्सलटेन्ट्स।
3. समस्त डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स।
4. एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी0, सूडा।
5. सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक